

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 374

दिनांक 20.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री की नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना यात्रा के परिणाम

*374. डॉ. मल्लू रवि:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के प्रधानमंत्री की नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना यात्रा का उद्देश्य, विशेषतः कच्चे तेल के क्षेत्र में भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना और व्यापार साझेदारी को मजबूत करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(ग) क्या तेजी से अपने पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ा रहे नाइजीरिया और गुयाना की यात्राओं के फलस्वरूप देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में नए समझौते या सहयोग होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ब्राज़ील में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी वैश्विक व्यापार और ऊर्जा साझेदारी में भारत के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश मंत्री

[डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर]

(क) से (ङ): वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

“प्रधानमंत्री की नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना यात्रा के परिणाम” के संबंध में दिनांक 20.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *374 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित वक्तव्य।

भारत और नाइजीरिया के बीच हार्दिक एवं सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और ये रिश्ते सार्थक राजनीतिक सहमति और विविधतापूर्ण आर्थिक सहभागिता के साथ एक “रणनीतिक साझेदारी” में विकसित हो गए हैं। नाइजीरिया अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत नाइजीरिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में भारत द्वारा मुख्यतः नाइजीरिया से कच्चे तेल का आयात किया जाता है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष नाइजीरिया से आता है। 16-17 नवंबर, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को मजबूत करने के विभिन्न तरीकों और साधनों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने 18-19 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। जी-20 रियो नेताओं का घोषणापत्र, जिसका भारत ने समर्थन किया, सितंबर 2023 में जी-20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान अंगीकृत जी-20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणापत्र के कई प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें वैश्विक व्यापार और ऊर्जा से संबंधित मुद्दे, भारत के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना और उसमें प्रगति करना शामिल है।

वैश्विक व्यापार के संबंध में, जी-20 रियो नेताओं के घोषणापत्र में अन्य बातों के साथ-साथ विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम-आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष, खुले, समावेशी, न्यायसंगत, सुदृढ़ और पारदर्शी, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा ऐसी नीतियों का समर्थन किया गया, जो व्यापार को सभी के लिए विकास एवं समृद्धि के माध्यम के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएं।

ऊर्जा के संबंध में, जी-20 रियो नेता घोषणापत्र में अन्य बातों के साथ-साथ स्वच्छ, टिकाऊ, न्यायसंगत, किफायती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तनों में तेजी लाने; मौजूदा लक्ष्यों और नीतियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार की औसत वैश्विक वार्षिक दर को दोगुना करने के प्रयासों के कार्यान्वयन का समर्थन करने; वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से विकासशील देशों में ऊर्जा परिवर्तनों के लिए वित्त पोषण की कमी को पूरा करने के लिए सभी वित्तीय स्रोतों और चैनलों से निवेश को उत्प्रेरित करने और बढ़ाने की आवश्यकता की पहचान करने; और महत्वपूर्ण खनिजों और स्रोत पर संवर्धित सामग्री, अर्धचालक और प्रौद्योगिकियों सहित ऊर्जा परिवर्तनों के लिए विश्वसनीय, विविध, टिकाऊ और जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

प्रधानमंत्री की गुयाना यात्रा के दौरान भारत और गुयाना के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में बढ़ी हुई भागीदारी के साथ, हमारे द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि के लिए आगे पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। 2021-22 में, कुल द्विपक्षीय व्यापार अपने चरम पर पहुंच गया और कच्चे तेल के आयात के कारण 223 मिलियन हो गया; भारत ने गुयाना से पहली बार 149 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कच्चा तेल आयात किया। इस करार का उद्देश्य हाइड्रोकार्बन क्षेत्र और सेवाओं की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है जिसमें एक-दूसरे के देशों में निवेश को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान एवं विकास, संयुक्त अध्ययन और मानव संसाधनों की क्षमता निर्माण शामिल है। भारतीय तेल कंपनियां गुयाना में अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में भाग लेने के अवसरों का भी लाभ उठा सकती हैं।
